MNCs and the number of such units that have partially closed their business or are on the verge of closure?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) Sir, 762 proposals including proposals from multinational companies have been approved in the consumer goods sector with the condition of dividend balancing. Proposals for increase in the foreign equity percentage in existing joint venture companies by way of acquisition of shares are considered by FIPB/Government only when they are supported by a Board Resolution of the target company. The acquisition of shares is as per SEBI/RBI guidelines. The information regarding closure of units in the private sector is not centrally maintained.

Revival of M/s Reyrolle Burn Ltd

2058. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to reply to Unstarred Question No. 1239 given in the Rajya Sabha on 8th June, 1998 and state:

(a) whether United Bank of India (UBI) has started implementing the scheme which was sanctioned on 16th October, 1997;

(b) if not, the action taken so far by Government;

(c) whether Government are required to provide need-based working capital if UBI has any reservation on extending the same as per the sanctioned scheme; and

(d) Government's action plan to ensure timely implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) to (d) United Bank of India (UBI) is yet to fulfil its commitment as per the sanctioned scheme. The bank has been requested several times by the Company and this Department to extend need based funds against Government counter guarantee in the overall interest of the company. The matter has been brought to the notice of BIFR for their intervention. In the meanwhile, GOI have released Rs. 395 lakh as per the sanctioned scheme, which is more than the amount envisaged in the Draft Rehabilitation Scheme viz Rs. 237 lakhs.

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनरूज्जीवित किया जाना

2059. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को पुनरूज्जीवित करने की योजनाएं अभी भी उनके मंत्रालय के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमो को पुनरूज्जीवित करने की योजनाओं को अन्तिम रूप देने में देरी के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे सहित इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बीआईएफआर को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधान के तहत संदर्भित करना अनिवार्य है। बीआईएफआर पुनरुद्धार प्लान तैयार करने के लिए एक ऑपरेटिंग एजेंसी की नियुक्ति करता है। बीआईएफआर कंपनी के पुनरुद्धार या अन्य बातों के लिए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, वित्तीय संस्थानों, श्रमिक संघों, प्रबंधकों इत्यादि सहित विभिन्न अभिकरणों के साथ परामर्श करता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची, जिनके पुनरुद्धार प्लान सरकार/बीआईएफआर द्वारा विचार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर है, संलग्न विवरण में दी गई (*नीचे देखिए*)

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम संचलन की समस्याओं का लगातार सामना करते रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ क्रयादेशों के प्राप्त करने

और पुनरुद्धार प्लान के अंतिम रूप देने में लंबित होने के कारण कार्यशील पूंजी की बाधा इत्यादि की वजह से निवेश की समय पर आपूर्ति होने में बाधा होना शामिल है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनके पुनरुद्धार प्लान सरकार/बीआईएफआर के विचाराधीन हैं

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नाम
1.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु० कंपनी लिमिटेड
2.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड*
3.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5.	प्रागा टूल्स लिमिटेड
6.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
7.	नेपा लिमिटेड*
8.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
10.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड

* सरकार ने इन उपक्रमों में पुनरुद्धार/पुनर्संरचना प्लान को पहले ही अनुमोदित कर दिया है जो बीआईएफआर की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे है।

Modernisation of Industrial clusters

2060. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the amount sanctioned and disbursed by Departments of SSI for technology development and modernisation of industrial clusters in India under UNIDO scheme; and

(b) the cluster in West Bengal which has been identified for modernisation and the fund allocated to it?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The UNIDO cluster development programme in India is a part of a global programme funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and executed by UNIDO. The programme activities started in India in May 1996 and completion is envisaged in December 2000. Besides the activities (seminars/workshops etc.) aiming at transferring the "Cluster development approach" at the national and state level, the programme has developed pilot projects in four clusters, namely Hand-printed Textiles of Jaipur (Rajasthan), Food Industry of Pune (Maharashtra), Cotton Hosiery of Tirupur (Tamil Nadu) and Woollen Knitwear of Ludhiana (Punjab). The amount spent on the programme in India till 31st December, 1998 is approximately US $ 350,000.

(b) There is no cluster in West Bengal that has been identified for modernisation under the programme so far.

लघु उद्योगों पर मंदी का प्रभाव

2061. **श्री ओम प्रकाश कोहली:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों पर मंदी का बहुत बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान 30 प्रतिशत है;

(ग) क्या फेडरेशन ऑफ दि एसोसिएशन्स ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष द्वारा लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है ताकि ऐसे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह करने में समर्थ बने रहे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) लघु उद्योग क्षेत्र में 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वर्षों में उत्पादन की विकास दर क्रमशः 11.40%, 11.32% और 8.43% रही है। इससे प्रतीत होता है कि लघु उद्योग मंदी के कारण बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं।